बिहार में जल जमाव

3422. **श्री आस मोहम्मद:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए कोई योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) बिहार में इस योजना के अंतर्गत क्या कार्यवाही की.गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) जल जमाव की समस्या का समाधान करने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है। बाढ़ को कम करने के संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत देश में जल निकास चैनलों के निर्माण समेत अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई थी। मार्च, 1991 के अंत तक इन कार्यों पर निम्नलिखित प्रगति हुई है।

(i) तटबंधों की लम्बाई - 15,764 कि.मी.
(ii) जल निकास चैनलों की लंबाई - 31,888 कि.मी.
(iii) सुरक्षा प्रदान किये गये शहर - 857 संख्या
(iv) सुरक्षा प्रदान किया गया क्षेत्र - 14.08 मिलियन हैक्टेयर

सातवीं पंचवर्षीय योजना (3/1990) के अंत तक देश में बाढ़ नियंत्रण उपायों के अन्तर्गत 2429.04 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(ग) उत्तरी बिहार की जल निकास संकुलता को दूर करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने गंडक और कोसी कमान क्षेत्रों में कुछ योजनाएं प्रारंभ की हैं। उत्तरी बिहार की जल निकास योजना की कुल अनुमानित लागत 450.59 करोड़ रुपए है। अब तक 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल निकास संकुलता से मुक्त किया गया है।

निम्नलिखित योजनाएं बनायी गई हैं।

क्रम सं.	योजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	व्यय (करोड़ रुपए)
1.	गंडक फेज (-II)	132.70	9.65
2.	कोसी फेज (-II)	81.64	19.86
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	15.60	8.84
4.	एकीकृत जल निकास परियोजना	220.65	0.27
	कुल	450.59	39.12

उत्तरी बिहार में बाढ़ पूंफिंग कार्यक्रम 100 करोड़
(जल निकास संकुलता निवारण समेत)

Irrigation Potential in Orissa

3423. SHRI SARADA MOHANTY.
SHRI RAHASBIHARI BARIK:

Will the Minister of WATER RESOURCES he pleased to state:

(a) the irrigation potential created in the State of Orissa by the end of the Seventh Five Year Plan;

(b) the additional irrigation potential proposed to be created in that State during the Eight Five Year Plan period and the achievements made so far;

(c) the steps taken to expedite the construction of the irrigation projects in Orrissa which have been pending from the previous plan period; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON): (a) and (b) Targets and achievements of irrigation potential created in Orissa are as under:

Period	Irrigation potential created (lakh hectares)
At the end of Seventh Plan	25.12
Target for Eight Plan	4.84
Achievements during 1992-94	1.05

(c) and (d) Irrigation being a State subject, irrigation projects are planned, funded and implemented by the respective State Government. However, the Eight Plan (1992—97) strategy envisages priority to completion of the on-going Major & medium projects.

गुजरात में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3424. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी:**
श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य के कच्छ जिले में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत और अधिक सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) गुजरात के कच्छ जिले में केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने का वर्ष	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)
1.	मित्ती	1985.86	2.36
2.	मतल	1985.86	2.21
3.	नारा	1990.91	2.31
4.	सुवी	1990.91	3.19
5.	निरूणा	1990.91	3.04
6.	कौला	1990.91	3.24

(ख) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास में शामिल करने के लिये गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हेक्टेयर)
1.	पिगुता सिंचाई योजना	481.84	1406
2.	बलदेवा	540.12	2240
3.	चोपादादाव	908.23	1460
4.	काकेडियाम्बा	812.88	891
5.	लखीगम	395.00	800

(घ) और (ङ) पिगट सिंचाई योजना और बलदेवा सिंचाई योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा इन्हें केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया है।

Irrigation Potential at the end of Seventh Plan

3425. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the state-wise irrigation potential created at the end of the Seventh Five Year Plan in the M & M Sector and subsequent year together with Government's investment on creating irrigaiton potentiality so far;

(b) whether it is a fact that Government have revised the irrigation potential created by the end of Seventh Plan from 34.8 mh to 29.9 mh as has been commented in the Economic Times of July 27-28, 1994 and the Annual Report of 1992-93, if so, what are the reasons and what are the facts in this regard; and

(c) what is the quantum of unutilised irrigation potential at the end of Seventh Plan and in the subsequent year. State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON): (a) and (c) A statement showing State-wise irrigation potential created an unutilised irrigation potential at the end of Seventh Plan and 1991-92 through Major & medium irrigation projects and plan expenditure during 1951—92 is given in the enclosed Statement.

(b) At the instance of Planning Commission, Irrigation Potential Created through Major & medium projects was reappraised at the end of Sixth Plan to correct the over-reporting and other inacccuracies on the basis of data furnished by State Governments. The potential created at the end of Sixth Plan was firmed up at 27.70 million hectares in place of the earlier figure of 30.01 million hectares. Accordingly, the figure of irrigation potential created at the end of Seventh Plan was revised at 29.92 million hectares and the same has been reflected in the Annual Report 1992-93.